



राज्यसभा की 10 सीट, एमएलसी चुनाव का प्लान... पीएम मोदी और सीएम योगी की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा !

(जीएनएस)। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डट नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग की. इस मीटिंग के दौरान मुख्य रूप से राज्यसभा, विधानसभा और एमएलसी चुनावों को लेकर अहम चर्चा हुई. राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर रणनीति पर बातचीत की गई.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब एक घंटे मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में राज्य में आगामी

विधानसभा, राज्यसभा और एमएलसी (MLC) चुनावों की तैयारियों पर चर्चा



हुई. बताया जा रहा है कि राज्यसभा की 10 सीटों में से ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति पर बातचीत हुई. इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनावों के बारे में जमीनी स्तर की जानकारी दी. बैठक में विधानसभा चुनावों की तैयारियों और भविष्य की रणनीतियों पर विचार-विमर्श हुआ.

बता दें, यूपी में अगला विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य की राजनीति तेजी से गमानें

लगी है. सीएम योगी का प्रधानमंत्री आवास पहुंचना और दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

जानकारों की मानें तो प्रधानमंत्री

और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली हर मीटिंग का अपना महत्व होता है, खासकर तब जब राज्य में चुनाव की तैयारियां की जा रही हो. यह मीटिंग आने वाले समय में पार्टी की दिशा और रणनीति को समझने के लिहाज

से काफी अहम मानी जा रही है. वहीं, उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान है. इसमें 5 स्नातक कोटे की और 6 शिक्षक क्षेत्र की MLC सीटें शामिल हैं. MLC चुनाव आम

विधानसभा चुनाव की तरह विधायकों के वोट से नहीं, बल्कि सीधे शिक्षकों और स्नातक मतदाताओं के वोटों से तय होता है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में उछड़ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में शहरों और गांवों के बीच दूरी में कमी आई है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आर्थिक मनोबल और आर्थिक सक्रियता बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वचुंअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और



सकारात्मक बदलाव के महत्व पर भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित और योगदान से ही हासिल किया जा

आईआईटी प्लेसमेंट से पहले बड़ा एक्शन, जॉब ऑफर देकर मुकरने वाली 22 कंपनियों पर लगाया बैन

(जीएनएस)। नई दिल्ली, देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में आगामी प्लेसमेंट सीजन शुरू होने से ठीक पहले बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है। छात्रों को नौकरी का ऑफर लेटर देकर बाद में मुकरने वाली 22 कंपनियों को अगले दो वर्षों के लिए कैम्पस प्लेसमेंट प्रक्रिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन कंपनियों ने पिछले शैक्षणिक सत्र में 2026 बैच के छात्रों को जॉब ऑफर तो थमा दिए, लेकिन बाद में मंदी या आंतरिक कारणों का हवाला देते हुए उन्हें पूरा नहीं किया या सीधे वापस ले लिया। इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये के चलते प्रभावित छात्रों को भारी मानसिक व करियर संबंधी तनाव झेलना पड़ा, जिसे देखते हुए संस्थानों ने यह संयुक्त कड़ा रुख अपनाया है। आईआईटी गुवाहाटी में एआईपीसी की बैठक में लिया गया कड़ा फैसला

छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ रोकने के लिए यह सख्त कदम इसी महीने की शुरुआत में आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित ऑल आईआईटी प्लेसमेंट कमेटी की बैठक में उठाया गया। आईआईटी

वह शीर्ष निकाय है जो देश के सभी 23 आईआईटी परिसरों में प्लेसमेंट और इंटरनशिप के नियम व दिशा-निर्देश तय करता है। हालांकि, पैनाल

दिवंगज टेक फर्म और स्टार्टअप पर गिरी गाज, ओरेकल का नाम भी चर्चा में



ने तकनीकी रूप से इसे 'ब्लैकलिस्टिंग' की जगह 'नॉन-कोऑपरेशन' (असहयोग) की श्रेणी में रखा है। एआईपीसी समन्वयक और आईआईटी गुवाहाटी के एसोसिएट प्रोफेसर जॉन जोस के अनुसार, इन 22 कंपनियों के चलते 23 आईआईटी संस्थानों के 150 से अधिक ऑफर प्रभावित हुए हैं। कुछ कंपनियों ने तो अकेले 10 से 15 तक ऑफर रद्द कर

कैम्पस सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, प्रभावित कंपनियों में अमेरिकी टेक दिग्गज ऑफ-कैम्पस ड्राइव के जरिए नई ओरेकल का नाम भी प्रमुखता से शामिल है, जिस पर दो साल के लिए असहयोग की कार्रवाई की गई है। कंपनी पर कथित तौर पर आईआईटी छात्रों को दिए गए लगभग 40 ऑफर्स को पूरा न करने का आरोप है। वैश्विक स्तर पर की गई बड़े पैमाने

की छंटनी का असर भारतीय कैम्पस भर्तियों पर भी दिखा। इसके अलावा लिस्ट में कई बड़े और चर्चित स्टार्टअप भी शामिल हैं, जिन्होंने कैम्पस में मोटी सैलरी पैकेज के वादे तो किए लेकिन समय आने पर छात्रों को ज्वाइनिंग देने से हाथ पीछे खींच लिए।

प्रभावित छात्रों के लिए आगे आए संस्थान, 30वें को मिली दूसरी नौकरियां

ऑफर रद्द होने से मुश्किल में फंसे छात्रों के लिए आईआईटी प्रशासन ने तुरंत बैकअप योजना पर काम शुरू किया है। प्लेसमेंट दफ्तरों ने प्रभावित छात्रों के सीवी अन्य रिक्रूटर्स और कॉर्पोरेट नेटवर्क के बीच सक्रिय किए हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे भी मिले हैं। अनुमान के मुताबिक, करीब 20 से 30 फीसदी छात्रों को वैकल्पिक माध्यमों और ऑफ-कैम्पस ड्राइव के जरिए नई नौकरियां मिल चुकी हैं। आईआईटी अधिकारियों का कहना है कि आगामी प्लेसमेंट सीजन में छात्रों के हितों की रक्षा के लिए नियमों को और अधिक कड़ा किया जा रहा है ताकि कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को हल्के में न ले सके।

'मोदी को मिले क्रेडिट, मानव इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ', ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने क्यों की जमकर तारीफ ?

ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने जो पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ की वो सही मालूम पड़ता है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 के बजट और कैबिनेट फैसलों के तहत अतिरिक्त मुफ्त कनेक्शन जारी करने के बाद उज्ज्वला योजना के तहत कुल एलपीजी कनेक्शनों की संख्या 10.58 करोड़ के पार पहुंच गई है।

(जीएनएस)। न्यूयॉर्क: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शासनकाल में जो कर दिखाया है वो मानव इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने ये बात भारत में करोड़ों लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच को लेकर कही है। एंथनी अल्बनीज ने कहा 'डट मोदी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि उनके कार्यकाल में भारत में जितने लोगों को ऊर्जा तक पहुंच मिली है उतनी मानव इतिहास के किसी भी दशक, किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश में नहीं मिली।' एंथनी अल्बनीज इस वक्त UNGA सम्मेलन में शिरकत करने अमेरिका गये हैं जहां एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत में ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने में पीएम मोदी की बड़ी कामयाबी की

तारीफ की। उन्होंने भारत में ऊर्जा तक पहुंच के अभूतपूर्व विस्तार का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया। उन्होंने 'पॉलिसी



इंस्टीट्यूट' को दिए इंटरव्यू में कहा 'भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत '

ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जो कहा है उसकी पुष्टि डेटा से भी होता है। जिसके अनुसार 1999 के बाद से कोयला, रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में बढ़ोतरी के साथ प्राइमरी एनर्जी सप्लाई तीन गुना से ज्यादा हो गई है।

भारत में इसे बदलाव के सबूत के तौर पर सराहा गया है जबकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ कंजर्वेटिव लोगों ने इसे पाखंडपूर्ण बताया क्योंकि भारत कोयले पर निर्भर है और ऑस्ट्रेलिया

रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। जबकि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों ग्रामीण और वंचित परिवारों तक बिजली और स्वच्छ ईंधन

आंकड़ा पार कर लिया है। भारत की कुल बिजली क्षमता में अब 52% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ स्वच्छ और हरित ऊर्जा का है। भारत ने यह मुकाम तय समय से पहले ही हासिल कर लिया है।

PIB के मुताबिक 2014 में जो सौर क्षमता महज 2.8 GW थी वह 2025-26 में अकेले 55.29 GW की नई क्षमता जुड़ने के बाद अब लगभग 168 गीगावाट (GW) तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही भारत सौर क्षमता में दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक सितंबर 2026 तक के ताजा डेटा के मुताबिक पीएम सूर्य घर योजना से 58 लाख से ज्यादा परिवार सीधे लाभान्वित हो चुके हैं और 49 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर (RTS) सफलतापूर्वक इंस्टॉल किए जा चुके हैं।

कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने जो पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ की वो सही मालूम पड़ता है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 के बजट और कैबिनेट फैसलों के तहत अतिरिक्त मुफ्त कनेक्शन जारी करने के मुताबिक भारत ने 304 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता (सौर, पवन, हाइड्रो और परमाणु) का

पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया है।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने अपने इतिहास में एक ही साल में सबसे अधिक 52.5 गीगावाट (GW) की नई बिजली क्षमता ग्रिड में जोड़ी जो अब तक का एक रिकॉर्ड है।

PIB की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2030 के अपने 500 GW के लक्ष्य की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। अगस्त 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 304 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता (सौर, पवन, हाइड्रो और परमाणु) का

एसआईआर के खिलाफ विपक्ष एकजुट: ममता और वामपंथी दल भी आए साथ, 'इंडिया' गठबंधन की 30 सितंबर को बैठक

एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। इस मुद्दे पर इंडिया ब्लाक की 30 सितंबर को बैठक होने वाली है। विपक्ष ने एसआईआर पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है

(जीएनएस)। नई दिल्ली: विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दल निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी चिंताओं तथा कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 30 सितंबर को यहां बैठक कर सकते हैं। यह बैठक ऐसे समय होगी, जब एसआईआर के विभिन्न पहलुओं को लेकर निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद की खबर सामने आई है और विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर

समन्वय बढ़ा है। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दल इस

(सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर पर तत्काल रोक



मुद्दे पर एक-दूसरे के संपर्क में हैं और संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं। कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भाकपा (माले)-लिबरेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त

लगावे की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को त्यागपत्र देकर इस मामले में सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) 29 सितंबर को बैठक कर इस मुद्दे पर अपनी रणनीति पर चर्चा करेगी।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंद्वी ममता वृणमूल कांग्रेस और माकपा को भी निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर एक साथ ला दिया है। माकपा महासचिव एम ए बेबी ने इस घटनाक्रम पर चर्चा के लिए 'इंडिया' गठबंधन और अन्य विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की थी। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि स्थिति में समन्वित कार्रवाई की जरूरत है।

विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने के लिए नया नोटिस देने की तैयारी में हैं। विपक्ष की ओर से कुमार को हटाने के लिए किया जाने वाला यह तीसरा प्रयास होगा।

'पीएम चुप्पी तोड़ें वरना माना जाएगा चोरों को संरक्षण', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का बड़ा हमला

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले पर कांग्रेस ने पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग करते हुए इसे 'चंदा चोरी, आस्था धोखा' करार दिया है। (जीएनएस)। नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुप्पी तोड़ने चाहिए और यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो 'चोरों' को उनका संरक्षण माना जाएगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में जांच में "बड़ी मछलियों" को बचाया गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष

और पारदर्शी जांच तथा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में मामले को 'चंदा चोरी, आस्था धोखा' करार देते हुए कहा कि आरोप पत्र में सामने आए तथ्यों से विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच और 'सरकारी लीपापोती' पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप पत्र में दर्ज घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा कि इस साल चार जून को गणना कक्ष के बाथरूम से 2.25 लाख रुपये मिलने का वीडियो ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय को भेजा गया था और अगले दिन उन्हें सीसीटीवी फुटेज



भी दिखाई गई थी। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि जब सीसीटीवी फुटेज, नकदी की बरामदगी और संदिग्ध कर्मचारियों की पहचान करार देते हुए कहा कि आरोप पत्र में सामने आ चुकी थी, तो 25 जून को प्राथमिकी दर्ज होने तक कथित तौर पर 21 दिन क्यों लगे? रमेश ने यह भी सवाल उठाया, 'एसआईटी की जांच में चढ़ावे की रकम को बिना अनुमति हटाने या छिपाने की 105 घटनाएं सामने आने के बावजूद जांच सिर्फ आठ आरोपियों तक ही क्यों सीमित रही? चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आरोपी बनाने के बजाय गवाह क्यों बनाया गया?'

कांग्रेस सांसद रमेश ने कहा कि मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था की निगरानी और प्रबंधन से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच के बिना मामले की पूरी सच्चाई सामने आना मुश्किल है। कांग्रेस महासचिव ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस मामले के तार बीजेपी-आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचते हैं। पूरी व्यवस्था की जवाबदेही नहीं तय की गई उन्होंने आरोप लगाया कि जांच की पहुंच "छोटे किरदारों" तक सीमित कर दी गई है और पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय नहीं की गई। रमेश ने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम पर आए चढ़ावे से जुड़े मामले में जिम्मेदारी तय होने तक इसे खत्म नहीं माना जा सकता।



गरवी गुजरात हिन्दी



JioTV CHENNAL NO. 2002



Jio Air Fiber



Jio tv+



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

सम्पादकीय

संस्थाओं की साख पर सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू एवं विवेक जोशी ने शनिवार को निर्वचन सदन में मिलकर कई महत्वपूर्ण फैसले ऐसे समय में लिए जब मुख्य चुनाव आयुक्त पर मनमाने तरीके से फैसले लेने के आरोप लग रहे हैं। आज की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों ने दिल्ली में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर जो बड़ा फैसला किया है उसके मुताबिक दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अन्तिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अब हर मामले में चुनाव पंजीकरण अधिकारी यानि ईआरओ के कार्यालय में जाकर सुनवाई में शामिल नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा बैठक में यह भी तय हुआ कि जिन लोगों को मतदाता सूची में नाम मैप नहीं होने या तार्किक गड़बिड़यों के कारण नोटिस दिया गया है, उनके घर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) जाएंगे। बीएलओ मतदाता के दस्तावेज एकत्र करके उन्हें ईसीआई नेट पर अपलोड करेंगे। इसके बाद ईआरओ यह फैसला करेगा कि मतदाता सूची में नाम रखने के लिए संबंधित व्यक्ति पात्र है अथवा नहीं। शनिवार को बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों ने यह भी तय किया कि जिला चुनाव अधिकारी रात में आश्रय स्थलों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों एवं बेघर लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में मदद के लिए डेस्क या शिविर लगाएंगे। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आनलाइन सुनवाई की सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा तथा यदि किसी मामले में सुनवाई जरूरी होती है तो मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से पेश होने के लिए अधिवृत कर सकता है।

चुनाव आयोग के मुखिया और दोनों सहयोगियों के बीच कितनी तनातनी रही इसका आकलन तो राजनेता ही कर रहे हैं किन्तु यदि चुनाव आयुक्त संधू और जोशी के विरोध के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश वुमार को यह बात समझ में आ गई कि एसआईआर कराने में बहुत ही सावधानी और धैर्य का परिचय देना होगा अन्यथा इस संवेदनशील मुद्दे पर देश में अलग-अलग वगरे में अलग-अलग तरीके से प्रतिब्रिया होगी।

राजनेता इसे अलग तरीके से देखेंगे तो मतदाता अलग तरीके से। दुनिया में यह संदेश जाएगा कि भारत में चुनाव फजी होते हैं क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त वुछ करने हैं और चुनाव अधिकारी को शिकायतों पर ध्यान देने वाला कोई प्रशासनिक तंत्र सत्रिय है ही नहीं।

सच तो यह है कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि छोटे-मोटे मतभेदों, गलतफहमी और आरोपों से उनके अस्तित्व को चुनौती नहीं मिलती। इस देश में सुग्राम कोर्ट के शीर्ष जजों में मतभेद सामने आए किन्तु कालान्तर में सब वुछ ठीक हो गया। फिर शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई के निदेशक और विशेष निदेशक वुत्ते-बिल्ली की तरह लड़े।

अब पता चला कि चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त और उनके दो साथियों में मतभेद है। इन तीनों के मतैक्य के अभाव का लाभ उठाकर अन्य अधिकारी अपनी सुविधानुसार फैसले ले रहे हैं और सारी जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त के मत्थे मड़ी जा रही है। शनिवार की बैठक संभव ही इसलिए हो पाई कि भारत में व्यक्ति नहीं संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। व्यक्ति आते हैं जाते हैं किन्तु लोकतांत्रिक संस्थाओं के अस्तित्व पर कोई संकट स्थाई रूप नहीं ले सकता। कारण मात्र यह है कि भारत का जनमानस ही लोकतांत्रिक भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है जिससे कोई भी व्यक्ति खुद को लोकतंत्र के लिए खतरा बनकर ज्यादा दिन स्वच्छन्दतापूर्वक रह ही नहीं सकता। इसलिए लोकतंत्र में विरोध के स्वर उठते रहने चाहिए चाहे वे स्वर आम जनता के बीच से उठें या राजनीतिक दलों के। विरोध के स्वर जब जिम्मेदारीपूर्वक उठते हैं तभी लोकतंत्र को फायदा होता है अन्यथा अराजकता की स्थिति पैदा होती है जो लोकतंत्र के लिए घातक साबित होती है।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अगस्त में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में करीब 25 प्रतिशत की हुई वृद्धि

नई दिल्ली ,26 सितंबर ,। भारत के इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात ने चालू वित्त वर्ष में लगातार पांचवें महीने मजबूत वृद्धि दर्ज की है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कार्डिसिल (ईईपीसी) इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि अगस्त में देश का इंजीनियरिंग निर्यात सालाना आधार पर 24.86 प्रतिशत बढ़कर 12.32 अरब डॉलर पहुंच गया।

उद्योग संगठन ईईपीसी इंडिया ने कहा कि भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात शीर्ष 25 प्रमुख बाजारों में से अधिकांश में बढ़ा है। केवल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब में निर्यात प्रभावित रहा, जिसका प्रमुख कारण पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई लॉजिस्टिक्स चुनौतियां थीं। इसके बावजूद अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख बाजारों में मांग मजबूत बनी रही।

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, 60 किमी प्रति घंटे तक चल सकती हैं हवाएं

(जीएनएस)।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ ने 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 26 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि झोंकों में गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 28 और 29 सितंबर को कहीं-कहीं बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 30 सितंबर को पश्चिमी प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत

(जीएनएस)।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। भजन क्लबिंग में पारंपरिक भजनों को कॉन्सर्ट जैसे माहौल में पेश किया जाता है। खासकर युवा इसमें भक्ति, संगीत और सामूहिक जुड़ाव का नया अनुभव तलाश रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित एक भजन क्लबिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ भजन का आनंद लिया। ये आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले जनवरी में 'मन की बात' कार्यक्रम में भी भजन क्लबिंग का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भारत में भजन और कीर्तन सदियों से संस्कृति की आत्मा रहे हैं। मंदिरों और कथाओं में भजन सुने जाते रहे हैं और हर दौर में लोगों ने अपने समय के अनुसार भक्ति को अपनाया है। अब नई पीढ़ी भक्ति को अपने अनुभवों और जीवनशैली से जोड़ रही है। इसी सोच से एक नया सांस्कृतिक चलन सामने आया है, जिसे 'भजन क्लबिंग' कहा जा रहा है।

ऐसे में आइए जानते हैं कि भजन क्लबिंग क्या है? युवाओं में इसकी दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है? भजन-कीर्तन की परंपरा का इतिहास क्या है? इसका क्या अरथ माना जाता है? भजन क्लबिंग में इससे कैसे अलग है? धार्मिक और आध्यात्मिक बाजार की क्या स्थिति है?

भजन क्लबिंग में भक्ति संगीत को आधुनिक कॉन्सर्ट जैसे माहौल में पेश किया जाता है। देश के अलग-अलग शहरों में युवा ऐसे आयोजनों में पहुंच रहे हैं। मंच को रोशनी और संगीत से सजाया जाता है और पूरा माहौल किसी बड़े कॉन्सर्ट जैसा दिखाई देता है, लेकिन यहां गाए जाने वाले गीत भजन होते हैं।

इन आयोजनों में आधुनिक संगीत वाद्ययंत्रों और स्टेज सेटअप के बीच कबीर के दोहे और मीरा के भजन भी

सुनाई देते हैं। यानी प्रस्तुति का अंदाज आधुनिक है, जबकि संगीत का आधार पारंपरिक भक्ति है।

प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक, मंच की सजावट, रोशनी और संगीत का अंदाज आधुनिक हो सकता है, लेकिन भजनों की भावना और उनके अर्थ को बनाए रखा जाता है।

युवाओं में क्यों बढ़ रही है लिचस्पी?

भजन क्लबिंग में युवाओं की भागीदारी खास तौर पर दिखाई दे रही है। 'बैकस्टेज सिब्लिंग्स' से जुड़े राघव के मुताबिक, उनके कार्यक्रमों में आने वाले दर्शकों में 18 से 28 वर्ष की उम्र के लोगों की हिस्सेदारी 85 फीसदी है। राघव के अनुसार, भजन क्लबिंग के जरिए देश की कला और संस्कृति का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों, भजनों से मिलने वाले सुकून और उनसे मिलने वाली सीख को समझ रहे हैं।

भजन-कीर्तन की परंपरा का इतिहास क्या है?

भजन और कीर्तन की परंपरा भारत में किसी एक समय या किसी एक व्यक्ति से शुरू नहीं हुई। इसका विकास लंबे समय में भक्ति, कविता और संगीत के मेल से हुआ। अलग-अलग क्षेत्रों में संतों और भक्त कवियों ने अपने आराध्य के प्रति भक्ति को गीत और सामूहिक गायन के जरिए व्यक्त किया।

भारत सरकार के सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी सीईआरआई के अनुसार, दक्षिण भारत के तमिल भाषी क्षेत्र में छठी-सातवीं शताब्दी के दौरान वैष्णव भक्ति साहित्य की मजबूत परंपरा विकसित हुई। इस दौर में 12 अलवार संत-कवियों ने भगवान विष्णु की भक्ति में गीतों की रचना की। इसी तरह छठी से आठवीं शताब्दी के बीच नयनार संत-कवियों ने भगवान शिव की स्तुति में भक्ति गीत लिखे।

इन रचनाओं के जरिए भक्ति को गीत और भावनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। मध्यकाल तक भक्ति साहित्य लगभग

सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में फैला।

मध्यकाल में भक्ति संगीत का विस्तार

मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के साथ भक्ति-काव्य और संगीत का



दायरा भी बढ़ा। अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में देवी-देवताओं की स्तुति से जुड़े पद और गीत रचे जाने लगे।

ब्रज क्षेत्र में इस परंपरा ने विशेष रूप लिया। भारत सरकार के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी आईजीएनसीए के अनुसार, 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के दौरान ब्रज में भक्ति-संगीत का महत्वपूर्ण विकास हुआ। पुष्टिमार्ग की उपासना पद्धति में कीर्तन को संगीत और दूसरी कलाओं के साथ जोड़ा गया।

चैतन्य महाप्रभु के दौर में कीर्तन 15वीं-16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव भक्ति परंपरा में कीर्तन को विशेष महत्व मिला। आईजीएनसीए के ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार, चैतन्य की परंपरा में कीर्तन संगीत और गायन के माध्यम से भक्ति का एक प्रमुख रूप था। इसे सार्वजनिक रूप से भी किया जाता था।

इस परंपरा में सामूहिक गायन और नाम-स्मरण महत्वपूर्ण हिस्सा बने। यही सामूहिक स्वरूप आगे संकीर्तन और नारकीर्तन जैसी परंपराओं में दिखाई देता है।

ब्रज और वृंदावन में भजन-कीर्तन

16वीं शताब्दी में वृंदावन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। आईजीएनसीए के अनुसार, वैष्णव भक्ति के प्रभाव से यहां भजन, कीर्तन,

तनाव, मूड, चिंता, अवसाद और पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जुड़े लक्षणों में सुधार करता है। इसके अलावा, चैंटिंग सामाजिक कल्याण, सामाजिक जुड़ाव और परीपकारी व्यवहार को भी बढ़ावा देता है।

भजन क्लबिंग में कैसा माहौल होता है?

बंगलूरु से मुंबई और दिल्ली से पुणे तक युवा ऐसे आयोजनों में पहुंच रहे हैं। ये कार्यक्रम पारंपरिक धार्मिक आयोजन की तुलना में कॉन्सर्ट जैसे दिखाई देते हैं। अंधेरे ऑडिटोरियम या कॉन्सर्ट हॉल में तेज रोशनी, सजा हुआ मंच और आधुनिक साउंड सिस्टम का इस्तेमाल होता है।

इन आयोजनों में सामूहिक गायन और भक्ति का अनुभव होता है। कृष्ण, शिव और राम से जुड़े भक्ति गीत आधुनिक साउंड सिस्टम और स्टेज लाइटिंग के बीच प्रस्तुत किए जाते हैं।

जेन जी और भक्ति का नया अनुभव

भजन क्लबिंग को जेन जी के बीच अपनी जड़ों, जुड़ाव और अर्थ की तलाश से भी जोड़ा जा रहा है। डिजिटल शोर, लगातार भागदौड़ और उपभोक्तावादी जीवनशैली से पैदा होने वाली थकान के बीच कुछ युवा ऐसे आयोजनों में शांति और जुड़ाव तलाश रहे हैं। यहां आध्यात्मिकता को एक ऐसे सामाजिक अनुभव के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें संगीत, सामूहिकता और भक्ति साथ दिखाई देते हैं।

सोशल मीडिया से बढ़ी पहुंच

भजन क्लबिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहे हैं। इन आयोजनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं और इनके जरिए नई पीढ़ी तक भक्ति संगीत और सांस्कृतिक विरासत की पहुंच बढ़ रही है।

आयोजकों के अनुसार, अलग-अलग शहरों में होने वाले ये कार्यक्रम बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। टिकट वाले आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भी दर्शकों की भागीदारी बढ़ने की बात कही गई है।

अलग-अलग पीढ़ियों को जोड़ता मंच
भजन क्लबिंग की एक खास बात इसकी समावेशिता भी बताई गई है।

एशियन गेम्स 2026 : अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला स्ववैश खिलाड़ी बनीं

(जीएनएस)।
नागोया , भारत की अनाहत सिंह ने जापान की दुनिया की छठे नंबर की खिलाड़ी सतोमी वातानाबे के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 3-2 (9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-13) से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही अनाहत ने एशियन गेम्स 2026 के महिला सिंगल्स स्क्वैश फाइनल में जगह बना ली है। अनाहत एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। 18 साल की भारतीय खिलाड़ी को शुरूआती दो गेम 9-11 और 11-13 से हारने के बाद कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने गेम प्वाइंट्स बचाकर और 8-10 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए तीसरा गेम 12-10 से जीतकर खुद को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद अनाहत ने चौथे गेम में शानदार वापसी की। 8-6 से



की बराबरी पर लाकर निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। भारतीय खिलाड़ी ने पांचवें और आखिरी गेम में दबदबा बनाया और इसे 11-3 से जीतकर

फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अनाहत की जीत से उनका मेडल पक्का हो गया है। यह युवा खिलाड़ी

इस कॉन्टिनेंटल इवेंट में अपना पहला सिंगल्स मेडल (गोल्ड या सिल्वर) जीतेगी। वातानाबे के तीसरे गेम हारने के बाद, मैच का रुख पूरी तरह से

भारतीय खिलाड़ी के पक्ष में हो गया। उन्होंने मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत की और बेहतरीन रैकेट कौशल दिखाते हुए आखिरी दो गेम में अपनी जापानी प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़ दिया।

अनाहत की जीत फाइनल के लिहाज से भी बहुत अहम है, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर लॉस एंजिल्स ओलंपिक में सीधे एंट्री मिलती है। अनाहत सिंह पिछली बार एशियन गेम्स में ब्रॉंज मेडल जीतने वाली महिला और मिकड टोम का भी हिस्सा थीं। यह युवा खिलाड़ी अब महिला सिंगल्स फाइनल के लिए कोर्ट पर उतरेगी। वहीं, मिकसड डबल्स जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सैथिलकुमार को सेमीफाइनल में हांगकांग, चीन की जोड़ी ली का यी और तांग गिंग हांग के खिलाफ हार मिली, जिसके चलते उन्हें ब्रॉंज मेडल से संतोष करना पड़ा।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

(जीएनएस)। लखनऊ, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया, आयोग के भीतर कथित असहमति और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र और नागरिक के मताधिकार का मूल आधार है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और वैधानिक होनी चाहिए।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 2 मार्च 2023 को अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर व्यवस्था निर्धारित की थी। उनके अनुसार अदालत ने कहा था कि जब तक संसद इस संबंध में कानून नहीं बनाती, तब तक नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके बाद दिसंबर 2023 में संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पदावधि से संबंधित कानून बनाया, जिसमें चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य को शामिल किया गया।कांग्रेस नेताओं ने फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार की मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को चयन समिति की बैठक हुई और उसी रात नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई। ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी को पदभरा संभाला। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया पर असहमति नोट दर्ज किया था। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी की आपत्तियों में मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटाए जाने का मुद्दा भी शामिल था।प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18(2) का हवाला देते हुए कहा कि आयोग का कामकाज जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से किया जाना है और मतभेद की स्थिति में बहुमत की राय

मान्य होती है। उनके अनुसार तीन सदस्यीय आयोग में दो-एक का बहुमत निर्णय के लिए पर्याप्त है तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल

अपने पद के आधार पर अलग निर्णायक मत का अधिकार नहीं दिया गया है।कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पिछले करीब 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने विभिन्न मामलों को लेकर कम से कम 14 लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने, मतदाता आंकड़ों और सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के केंद्रीकरण सहित कई विषय शामिल बताए गए। उन्होंने कहा कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने निर्णयों की जानकारी उन्हें नहीं दिए जाने को लेकर भी शिकायत की थी। कांग्रेस नेताओं के अनुसार मई से अगस्त 2026 के बीच आयोग की पूर्ण बैठक नहीं हुई और 9 सितंबर को चार महीने बाद पूर्ण बैठक हुई।प्रेस वार्ता में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की ओर से दर्ज की गई असहमति का भी उल्लेख किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ भाषणों से जुड़े आदर्श आचार संहिता के मामलों में आयोग द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के दौरान लवासा ने असहमति दर्ज की थी। उन्होंने अपनी अत्यंत राय को रिकॉर्ड में शामिल किए जाने की मांग को लेकर तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भी लिखे थे।कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि

एसआईआर का पहला चरण जून से सितंबर 2025 के बीच बिहार में हुआ, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 4 नवंबर 2025 से हुई।

प्रक्रिया और नई अनिवार्य शर्तों का वैधानिक आधार भी स्पष्ट होना चाहिए।उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 और 327 के बीच संबंध का



तीसरे चरण को 30 मई 2026 से जारी बताया गया। कांग्रेस नेताओं के अनुसार तीनों चरणों में 26 राज्य और छह केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं तथा इस दौरान बड़ी संख्या में मतदाता नाम हटाए जाने और मतदाताओं से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाने का दावा किया गया।फॉर्म छह में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह नए मतदाता के पंजीकरण का वैधानिक प्रपत्र है और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित है। उनके अनुसार इसमें आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली एसआईआर सूची में होने से संबंधित नया सवाल जोड़ा गया। कांग्रेस ने दावा किया कि मई 2026 में विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आपत्ति दर्ज की थी और सुखबीर सिंह संधू ने भी इसका समर्थन किया। कांग्रेस नेताओं के अनुसार संधू ने 13 अगस्त को इसे 'अनिधिकृत और अवैध' बताते हुए हटाने की मांग की थी।कांग्रेस ने एसआईआर के कानूनी आधार पर भी सवाल उठाते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) का उल्लेख किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस प्रावधान के तहत निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी हिस्से की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश दे सकता है, लेकिन इस अधिकार के प्रयोग के दौरान अपनाई जाने वाली

उल्लेख करते हुए कहा कि अनुच्छेद 327 संसद को चुनाव और मतदाता अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की संवैधानिक जिम्मेदारी देता है। कांग्रेस नेताओं ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ए.सी. जोसा बनाम सिवन पिल्ले मामलों का हवाला देते हुए कहा कि जहां कानून मौन हो, वहां आयोग अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून और उसके अनुरूप बनाए गए नियमों के विपरीत आदेश जारी करने की सीमा पर संवैधानिक प्रश्न उठते हैं।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनका मुख्य सवाल केवल यह नहीं है कि निर्वाचन आयोग के पास एसआईआर कराने की शक्ति है या नहीं, बल्कि यह है कि मतदाता सूची जैसे लोकतंत्र के मूल आधार से जुड़े निर्णय कितनी पारदर्शिता, वैधानिक प्रक्रिया और संस्थागत सहमति के साथ लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आयोग के भीतर किसी प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां दर्ज हुई हैं तो उन आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया और उसके आधार को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।।प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन कुंवर सिंह निषाद और मीडिया समन्वयक पूर्वी क्षेत्र पुनीत पाठक भी मौजूद रहे।

मूसलाधार बारिश के बीच डीएम और नगर आयुक्त ने शहर का किया निरीक्षण, जल निकासी व्यवस्था परखी



(जीएनएस)। लखनऊ, शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच जिलाधिकारी विशाख जी और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल निकासी और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने मौके पर व्यवस्थाओं को परखते हुए संबंधित अधिकारियों को जलभराव की स्थिति से निपटने और जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जोन-4 में ताज अंडरपास, गोमती नगर पंपिंग स्टेशन, जनेश्वर मिश्र रेलवे अंडरपास तथा कटौता झील के निकट सपना स्वीट्स क्षेत्र का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने जल निकासी की व्यवस्था, पंपिंग स्टेशन की कार्यप्रणाली और बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद

जोन-3 स्थित जानकीपुरम पंपिंग स्टेशन और बैरल नंबर-2, बंधा रोड का भी निरीक्षण किया गया। संबंधित टीमों से जल निकासी और पंपिंग व्यवस्था की जानकारी लेते हुए अधिकारियों ने लगातार सतर्क रहने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।नगर निगम की टीमें शहर के सभी जोनों में लगातार सक्रिय हैं और जलभराव की आशंका वाले क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। विभिन्न स्थानों पर नालियां और जल निकासी मार्गों की सफाई कराई जा रही है, जिससे बारिश के पानी की निकासी सुचारु बनी रहे। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में नगर निगम की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और जलभराव रोकने के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जल निकासी, सफाई समेत अन्य जरूरी कार्यों में टीमें लगातार जुटी हुई हैं। निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी

और नगर आयुक्त ने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम पहुंचकर बारिश से संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी का जायजा लिया। कंट्रोल रूम के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता के अनुसार संबंधित टीमों को मौके पर भेजकर कार्रवाई की जा रही है।जिलाधिकारी विशाख जी ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के कारण जिन भी क्षेत्रों में पेड़ गिरने की सूचना मिले, वहां संबंधित टीम को तत्काल भेजकर पेड़ हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि यातायात और आमजन की आवाजाही प्रभावित न हो।नगर निगम ने बारिश और जलभराव से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए नियंत्रण कक्ष का डोल फ्री नंबर 1533 जारी किया है। इसके अलावा नागरिक 9219902911, 9219902912, 9219902913 और 9219902914 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से

अपील की है कि बारिश के दौरान जलभराव, पेड़ गिरने अथवा किसी अन्य समस्या की सूचना तत्काल नियंत्रण कक्ष को दें, ताकि संबंधित टीम को मौके पर भेजकर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

पद्मश्री डॉ. अनिल रस्तोगी समेत विभिन्न क्षेत्र की महान विभूतियां सम्मानित

-खुशी फाउंडेशन व दिशा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में पीएसआई इंडिया के सहयोग से सेवा शिखर सम्मान समारोह आयोजित

-समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए ऐसे आयोजन जरूरी : प्रो. संजय द्विवेदी लखनऊ, खुशी फाउंडेशन और दिशा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पी. एस. आई. इंडिया) के सहयोग से शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के सभागार में विशेष सेवा शिखर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कला-संस्कृति, चिकित्सा, खेल, समाजसेवा, महिला सशक्तिकरण, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों की महान विभूतियों को सेवा शिखर और सेवा गौरव सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओ. पी. श्रीवास्तव रहे। समारोह की अध्यक्षता भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी ने की।

कोहली पेट्रोल पंप पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कर्मचारी मामूली झुलसा

(जीएनएस)।

लखनऊ, आलमबाग थाना क्षेत्र के चंदर नगर चौकी अंतर्गत एसबीआई रोड स्थित कोहली पेट्रोल पंप पर शनिवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण मामूली आग लग गई। सूचना मिलते ही आलमबाग पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

आग को पेट्रोल पंप पर उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की मदद से तत्काल बुझा दिया गया।पुलिस के अनुसार 26 सितंबर को करीब 13:30 बजे डायल-112 के माध्यम से पेट्रोल पंप पर आग लगने की सूचना मिली थी।

मौके पर जांच में पता चला कि

डीजल टैंक के पास स्थित एक छोटे टैंक में बारिश का पानी भर गया था। पेट्रोल पंप का कर्मचारी बाल्टी से पानी बाहर निकाल रहा था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने से लोहे की रॉड में चिंगारी निकली और उससे मामूली आग लग गई।कर्मचारियों ने तत्काल उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों का

इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग की लपट लगने से एक कर्मचारी के हाथ में मामूली चोट आई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक स्थिति सामान्य है और मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम है।

छत की मरम्मत करने चढ़े बुजुर्ग की मलबे में दबकर मौत

(जीएनएस)।

लखनऊ, बीकेटी थाना क्षेत्र के ग्राम भौली में शनिवार दोपहर मकान की छत गिरने से 65 वर्षीय बजरंगी यादव की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस

मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की।पुलिस के अनुसार 26 सितंबर को करीब दोपहर दो बजे ग्राम भौली में बजरंगी यादव पुराने मकान की छत की मरम्मत करने के लिए ऊपर चढ़े थे। बताया गया कि छत से

पानी आदि टपक रहा था, जिसके चलते वह उसकी मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक छत भरभराकर गिर गई और वह मलबे में दब गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।स्थानीय लोगों के अनुसार बजरंगी

यादव को गांव में ही एक सरकारी आवास आवंटित था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

मनीष कुमार बने आईटीएसए उत्तर प्रदेश पूर्व अध्याय के अध्यक्ष

..लखनऊ(जीएनएस)। भारतीय दूरसंचार सेवा के 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी और दूरसंचार विभाग, उत्तर प्रदेश पूर्व एलएसए के अपर महानिदेशक मनीष कुमार को इंडियन टेलीकॉम सर्विस एसोसिएशन (आईटीएसए) के उत्तर प्रदेश पूर्व अध्याय का अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। उनके निर्वाचन के अवसर पर आयोजित बैठक में आईटीएसए के वरिष्ठ सदस्य जीसी राय, राजेश कुमार, डीके मिश्रा, प्रसून चंद्रा, अरविन्द कुमार तथा सर्किल सचिव बीरेन्द्र मौर्य सहित अध्याय के कई सदस्य उपस्थित रहे।बैठक में देश

में हो रही डिजिटल क्रांति में भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि देश के दूरसंचार तंत्र की तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में इन अधिकारियों की

महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अत्याधुनिक नेटवर्क की स्थापना, निर्बाध दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने से लेकर डिजिटल सशक्तिकरण को आम लोगों तक पहुंचाने में अधिकारियों ने योगदान दिया है।बैठक



में उत्तर प्रदेश पूर्व क्षेत्र के सुदूर और ग्रामीण इलाकों तक अंतिम छोर तक व्यापक इंटरनेट संपर्क पहुंचाने तथा देश में पांचवीं और छठी पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक के त्वरित विस्तार से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई।

इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र के सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन को भंग किए जाने पर सदस्यों ने चिंता और निराशा व्यक्त की।इंडियन टेलीकॉम सर्विस एसोसिएशन भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारियों का प्रतिनिधि

खाद्य प्रसंस्करण से किसानों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे: केशव प्रसाद मौर्य

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतिगत एवं प्रोत्साहनात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत उपलब्ध सुविधाओं, प्रोत्साहनों और अनुदान की व्यापक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी इस क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आए।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलने से किसानों के उत्पादों को बेहतर बाजार और अधिक मूल्य मिल सकेगा तथा कृषि आधारित उद्योगों को मजबूती मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों तक औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में निवेश की लगातार प्रोत्साहित कर रही है।केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और

विस्तार से जुड़े निवेश प्रस्तावों के त्वरित परीक्षण की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 में प्रदेश में पूंजी निवेश आकर्षित करने के साथ कृषि उत्पादों



के मूल्य संवर्धन, आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। नीति के तहत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, दुग्ध प्रसंस्करण, तैयार खाद्य एवं पकाने के लिए तैयार उत्पाद, नाश्ता उत्पाद, नमकीन, बेकरी, अनाज, दाल और तिलहन प्रसंस्करण सहित विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के डासप सभागार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत गठित मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। बैठक वर्युअल माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त नई

परियोजनाओं के प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन किया गया।बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन पोर्टल पर कुल 16 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 10 परियोजना प्रस्ताव समिति के समक्ष रखे गए। समिति ने इन परियोजनाओं का नीति के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय परीक्षण के अनुपालन के साथ सभी 10 प्रस्तावों को आगे की कार्रवाई के लिए राज्य स्तरीय सशक्त समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गई।समिति के समक्ष प्रस्तुत परियोजनाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र, फल पेय एवं जूस निर्माण, सब्जी एवं मसाला उत्पाद, फल एवं सब्जी सॉस, नमकीन एवं अन्य खाद्य उत्पाद, स्नैक्स निर्माण, पशु आहार निर्माण तथा चिप्स और दाल-खिचड़ी निर्माण से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

परियोजनाओं के परीक्षण के दौरान समिति ने कच्चे माल की उपलब्धता, स्थानीय किसानों से कच्चे माल की आपूर्ति, प्रस्तावित उत्पादन

क्षमता, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक वैधानिक अनुमतियों और अभिलेखों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया। संबंधित इकाइयों को आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण-पत्र निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रस्तावों की आगामी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।बताया गया कि प्रस्तावित परियोजनाओं से प्रदेश में कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन बढ़ेगा और किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।अपर मुख्य सचिव बी.एल. मीणा ने समिति के सदस्यों और संबंधित अधिकारियों को परियोजना प्रस्तावों से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यमियों से भी नीति के प्रावधानों और निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की।उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के माध्यम से प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत अनुदान, शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन ढांचे, पिछड़े एवं अग्रिम संपर्क तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं।

विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह ने कहा कि समाज की प्रगति केवल संसाधनों से ही नहीं बल्कि उन लोगों के समर्पण, साहस और निरन्तर प्रयासों से होती है, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने कार्यक्षेत्र में असाधारण योगदान देते

विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह ने कहा कि समाज की प्रगति केवल संसाधनों से ही नहीं बल्कि उन लोगों के समर्पण, साहस और निरन्तर प्रयासों से होती है, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने कार्यक्षेत्र में असाधारण योगदान देते

समारोह के विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री शिव भूषण सिंह ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के जीवन की असल पूँजी होती है, जिसकी सुविधा मुहैया कराने में यह संस्थाएं जुटी हैं, जो कि सराहनीय है। इस मौके पर विशेष



हैं।विशिष्ट अतिथि पी. एस. आई. इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर समरेन्द्र बेहरा ने कहा कि सम्मान व्यक्ति के कठिन परिश्रम, समर्पण और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का एक प्रमाण होता है। विभिन्न क्षेत्रों की जिन महान विभूतियों को यहाँ सम्मानित किया गया वह उनके कार्यों को सराहा। समारोह के

बी. भट्ट, अनुभवी चिकित्सक व श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित लेखिका, रणनीतिकार, कौशल विकास विशेषज्ञ एवं प्रेरणादायी महिला नेतृत्वकर्ता निशा सिंह, एसजी पीजीआई की डॉ. निरुपमा सिंह, समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पी.एस.आई. इंडिया व समाजसेवी डॉ. उर्वशी साहनी, खेल के क्षेत्र में वर्ष 1988 के सियोल ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले सुजीत कुमार, पत्रकारिता के क्षेत्र में रमा अरुण त्रिवेदी, आदर्श प्रकाश सिंह, मनीष पाण्डेय, हरी मोहन वाजपेयी 'माधव' व दिनेश श्रीवास्तव, शिक्षा के क्षेत्र में श्री जय नारायण मिश्रा पी.जी. कॉलेज, लखनऊ के प्राचार्य प्रो. कौशल किशोर शुक्ला, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के समाजशास्त्र विभाग की सहायक आचार्य डॉ. शिवानी कटारा, उद्यमिता के क्षेत्र में सीधु श्रीवास्तव, कृषि के क्षेत्र में इनवायन्यान नगरी ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को सम्मानित किया गया।

सेवा गौरव सम्मान से सम्मानित

